

कैबिनेट

राज्य मंत्रिमंडल ने पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत पशुपालन विभाग में मल्टी टास्क वर्कर पशु मित्र के एक हजार पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस दौरान स्कूलों में पुस्तकालयों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पुस्तकालय के सौ पद भरने को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य में क्षरित वन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर के तहत निजी उद्यमियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई। इस दौरान नगर निगम शिमला में घाटी की ओर भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी गई। मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला में माता तारा देवी मंदिर के साथ लगते वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के तहत हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया है। बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने को भी स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की केंद्र सरकार से मांग की है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भी लिखेंगे और 24 मई को दिल्ली में उनसे मुलाकात कर इस विषय को उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुर्की से सेब आयात होने के कारण हिमाचल प्रदेश के बागवानों को सेब का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है, उसने हिमाचल के बागवानों को प्रभावित किया, इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस मामले में व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी में प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहां के बागवानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जब बाहर से आयात सेब आता है तो हमारे सेब के दाम प्रति किलो के हिसाब से गिर जाते हैं, हम चाहेंगे कि तुर्की के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी शिमला में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अभी और सरकारी दफ्तरों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है जबकि विभागों को स्थानांतरित करने की अभी कोई योजना नहीं है।

विक्रमादित्य सिंह

लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण- 4 के तहत बनने वाली सड़कों की अपग्रेडेशन का काम तेजी से चल रहा है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि डिविजन स्तर पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि समय अवधि के भीतर काम पूरा किया जाए और बिना वजह काम में देरी पर कार्रवाई की जाएगी। लोकनिर्माण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में डीपीआर बनाने और नारेडा पोर्टल पर हिमाचल देश में टॉप पर है, लेकिन हिमाचल को सड़कें न मिलने में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण की है। उन्होंने लोगों से सड़क निर्माण में जमीन देने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में अभी तक की जो हमारी डीपीआर्स बनी है,अभी तक जो हमने नरेडा जो उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पीएम जेएसआई का वहां पे जो अपलोड किया है अभी मास में उसमें हिमाचल इज द टॉप परफॉर्मर पूरे देश के तुलना मेंऔर हिमाचल को अधिकतर सड़के इसमें मिल सकती है मगर जो हमको हैंडीकैप देखने को मिल रहा है जगह-जगह पे वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉरेस्ट की समस्याओं एफसीए

एफआरएऔर साथ में जो जमीन पीडब्ल्यूडी के विभाग के नाम पर नहीं है वो हमको हैंडीकैप मेंआज ये अपील कर रहा हूंअगर सबका सहयोग मिलेगा तो हम इस आंकड़े को करीबन 1500 किलोमीटर तक खींच सकते हैं

प्रदर्शनी

केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय, द्वारा शिमला के रिज़ मैदान पर 'एकता' प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आज शुरू हुई इस प्रदर्शनी का शुभारम्भ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने किया। 26 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर के स्वयं सहायता समूहों व उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के 70 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। इस दौरान प्रबोध सक्सेना ने कहा कि टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा इस तरह का आयोजन करवाना काफी सराहनीय है।

सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन जो है वो शिमला में किया है, राज सरकार जो है वो उनके प्रति बहुत कृतज्ञ है कि उन्होंने शिमला को चूज किया इस एक्सिबिशन के लिए और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यहां पर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कृतियां हैं वो लोगों को देखने को मिलेंगी तो मैं समझता हूं कि ये जो शिमला वासियों के लिए और जो यहां पर्यटक आएंगे इस सीजन में उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण

इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की ट्रेड एडवाइजर सुशुभ्रा ने बताया कि 'एकता' प्रदर्शनी का उद्देश्य देशभर के कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प उद्यमियों को साझा मंच प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि 21 मई तक गेयटी थिएटर में तीन दिवसीय ज्ञान सत्र और कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं।
